युवाओं को रोजगार देने संकल्पबद्ध सरकार, भर्ती प्रक्रिया शीघ्रः डॉ. यादव

प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने के आदेश जारी, वर्ष-वार भर्ती कैलेंडर जारी

भोपाल (काप्र)।

राज्य शासन अगले 5 वर्षों में 2 लाख 50 हजार सरकारी नौकरियां उपलब्ध कराने प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के सीधी भर्ती के रिक्त पदों की पूर्ति करने के आदेश जारी कर दिए हैं। रिक्त पदों पर भर्ती के लिए हर साल सरकारी परीक्षा कैलेंडर जारी किया जायेगा।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार ने संकल्प पत्र-2024 के बिन्दु रोजगार के अवसर में युवाओं को सरकारी नौकरियों में सेवा का अवसर देने संकल्प दोहराया है। इस संकल्प को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए सरकारी नौकरियों में भर्ती की सभी औपरिकताएं पूरी की जा रही हैं और जल्दी ही भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू की जायेगी। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने सभी विभागों को भर्ती की प्रक्रिया संबंधी औपचाकिताएं पूरी करने के निर्देश दिये हैं, जिससे वर्षवार भर्ती की प्रक्रिया बिना रूकावट पूरी की जा सके। राज्य शासन के इस निर्णय से सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पहले जारी निर्देश एवं आदेश निष्प्रभावी होंगे लेकिन पहले जारी आदेशों, परिपत्रों के आधार पर ऐसे रिक्त पदों पर, जिन पर विभागों द्वारा दिनांक 30 अक्टूबर तक भर्ती की कार्यवाही कर दी गई है, वह निरस्त नहीं मानी जायेगी। इनमें सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए कार्यवाही कर्मचारी चयन मण्डल, म.प्र. लोक सेवा आयोग/ अन्य संस्था को प्रेषित किये गये हैं। इसके अलावा नियुक्ति की जा चुकी है परंतु कार्यभार ग्रहण किया जाना शेष है या परीक्षा परिणाम के आधार पर नियुक्ति पत्र जारी किया जाना शेष है। मुख्य रूप से संवर्ग में स्वीकृत पदों के आधार पर 5प्रतिशत पदों की ही सीधी भर्ती से पदपूर्ति करने के लिए प्रशासकीय विभाग को अधिकृत किया गया है। यह परिपत्र वर्ष 2028-29 तक के लिये स्थगित किया जाता है। राज्य शासन द्वारा प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी के सीधी भर्ती के रिक्त पदों की पूर्ति गणना के संबंध में मार्गदर्शन दिया गया है। इसके अनुसार सर्वप्रथम प्रत्येक संवर्ग में 1 अप्रैल 2024 की स्थिति में सीधी भर्ती के रिक्त पदों की गणना की जायेगी। इनमें ऐसे पद जिनके संबंध में कार्यवाही कर्मचारी चयन मंडल/ एमपीपीएससी या अन्य संस्थाओं में प्रचलन में है, रिक्त पदों की गणना में शामिल नहीं किए जायेंगे। ऐसे 13 प्रतिशत पद जो पिछड़ा वर्ग के लिए अंतिम परीक्षा परिणाम के बाद रोके गए हैं, इनको भी रिक्त पदों की गणना में नहीं लिया जायेगा।

ऐसे संवर्ग जिनमें रिक्त पदों की संख्या 1 से 50 तक है, की पद पूर्ति दो चरणों में की जायेगी (अर्थात 50प्रतिशत पद वित्तीय वर्ष 2024-25 में एवं शेष 50प्रतिशत पद वित्तीय वर्ष 2025-26 में भरे जायेंगे)। ऐसे संवर्ग जिनमें रिक्त पदों की संख्या 51 से 200 तक है, उनमें पद पूर्ति तीन चरणो में आधार पर की जायेगी। यदि 33प्रतिशत से कम है, तो एक बार में रिक्त पदों की पूर्ति, यदि 33प्रतिशत अथवा अधिक है पर 66प्रतिशत से कम है तो वर्षवार पदपूर्ति होगी। प्रथम वर्ष 2024-25 में 8 प्रतिशत द्वितीय वर्ष 2025-26 में 46प्रतिशत और तृतीय वर्ष 2026-27 में 46प्रतिशत की पदपूर्ति होगी। यदि रिक्त पदों की संख्या यदि 66प्रतिशत अथवा अधिक है तो वर्षवार पदपूर्ति में, प्रथम वर्ष 2024-25 में 8प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 2025-26 में 31प्रतिशत, तृतीय वर्ष 2026-27 में 31प्रतिशत, चतुर्थ वर्ष 2027-28 में 30प्रतिशत भर्ती होगी।

ऐसे संवर्ग जिनमें रिक्त पदों की संख्या 200 से अधिक है वहां पदपूर्ति के संबंध में निम्न सिद्धांत अपनाए जायेंगे। सीधी भर्ती के रिक्त पदों की संख्या यदि 25प्रतिशत से कम है, तो एक बार में रिक्त पदों की पूर्ति होगी। यदि 25प्रतिशत अथवा अधिक है, पर 50प्रतिशत से सीधी भर्ती के रिक्त पद कम है तो वर्षवार पदपूर्ति होगी। इसमें प्रथम वर्ष 2024-25 में 8प्रतिशत, दूसरे साल 2025-26 में 46प्रतिशत और तीसरे साल 2026-27 में 46प्रतिशत पदों की पूर्ति होगी। रिक्त पद यदि 50प्रतिशत या उससे अधिक या 75प्रतिशत से कम है, तो प्रथम वर्ष 2024-25 में 8प्रतिशत, दूसरे साल 2025-26 में 31प्रतिशत, तीसरे साल 2026-27 में 31प्रतिशत और चौथे साल 2027-28 में 30प्रतिशत पदों की पूर्ति होगी। इसी प्रकार यदि रिक्त पर 75प्रतिशत या उससे ज्यादा है, तो प्रथम वर्ष 2024-25 में 8प्रतिशत, सीधी भर्ती के कुल पद द्वितीय वर्ष 2025-26 में 23प्रतिशत तृतीय वर्ष 2026-27 में 23प्रतिशत, चतुर्थ वर्ष 2027-28 में 23प्रतिशत, और वर्ष 2028-29 में 23प्रतिशत पदों पर भर्ती होगी।

डाईंग संवर्गों में भर्ती नहीं

राज्य शासन द्वारा डाईंग संवर्ग घोषित किये जा चुके संवर्गों में किसी भी प्रकार से कोई भर्ती नहीं की जायेगी। अनुबंधित वाहन के लिए वाहन चालको के पद पर सीधी भर्ती आवश्यक नहीं है। जिन विभागों के पास स्वयं के वाहन है, वे भी वाहन चालक के कार्य हेतु सेवायें आउटसोर्स के माध्यम से प्राप्त करने पर विचार करें। विशिष्ट विभाग जहाँ वाहन चालकों के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती अतिआवश्यक है, वे वित्त विभाग को तथ्यों सहित प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुये स्वीकृति प्राप्त करें।

राज्य शासन के विभिन्न कार्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के पदों के विरूद्ध कार्य करने के लिये व्यक्तियों की पूर्ति आउटसोर्स पर करने के लिए चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों की सेवायें प्राप्त करने संबंधी नीति-निर्देश के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। विशिष्ट विभाग जहाँ चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती अतिआवश्यक है, वे वित्त विभाग को तथ्यों सहित प्रस्ताव प्रेषित करते हुये स्वीकृति प्राप्त करेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिये गये हैं कि रिक्त पदों की पूर्ति के समय कैडर मैनेजमेंट प्रभावित न हो।

ग्रामीण विकास उत्सव, उत्पादों और कारीगरों के प्रोत्साहन का प्रभावी मंच : राज्यपाल

विभिन्न राज्यों के स्टॉल्स का अवलोकन और कारीगरों से किया संवाद

भोपाल (काप्र)।

राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा है कि ग्रामीण विकास उत्सव, देश भर के कारीगरों और प्रसिद्ध उत्पादों के प्रोत्साहन का प्रभावी मंच है। ऐसे आयोजन ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। राज्यपाल श्री पटेल नाबार्ड द्वारा भोपाल हॉट बाजार में आयोजित ग्रामीण विकास उत्सव के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने 19 से 27 नवम्बर तक आयोजित हो रहे ग्रामीण विकास उत्सव का फीता काटकर शुभारंभ किया।

श्री पटेल ने विगत 6 वर्षों से देशभर के कारीगरों के प्रोत्साहन के लिए उत्सव का आयोजन करने पर नाबार्ड को बधाई दी। उन्होंने कहा कि नाबार्ड ऐसे आयोजनों का व्यापक और सघन स्तर पर प्रचार-प्रसार करें। राज्यपाल श्री पटेल ने स्थानीय मीडिया से भी अपील की कि देश के कारीगरों के उत्पादों के प्रचार-प्रसार में भरपूर सहयोग करें।

राज्यपाल ने कहा कि नाबार्ड, सूक्ष्म उद्यमिता विकास कार्यक्रम, आजीविका एवं उद्यमिता विकास कार्यक्रम और गैर कृषि उत्पादक संगठन बनवाने जैसे विकास के महत्वपूर्ण प्रयास कर रहा है। कृषि, कुटीर, ग्रामीण एवं लघु उद्योगों हस्तशिल्प के विकास परक कार्यों के द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती और समृद्धि में प्रभावी योगदान दे रहा है। नाबार्ड द्वारा स्व-सहायता समूह की महिलाओं, हस्तशिल्पियों और कृषक उत्पादक संघों के सदस्यों के लिए कौशल विकास की कई योजनाएं भी चलाई जा रही है। श्री पटेल ने कहा कि हमारे देश की आत्मा गांवों में बसती है। जब आत्मा मजबूत होगी तभी पूरा शरीर यानि हमारा देश मजबूत, सक्षम और आत्म-निर्भर होगा। उन्होंने नाबार्ड के ग्रामीण युवाओं के कौशल उन्नयन के द्वारा सम्मानजनक आजीविका पाने के प्रयास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती की दिशा में सार्थक कदम बताया।

राज्यपाल श्री पटेल ने योजनाओं में प्रशिक्षित ग्रामीण किसानों, महिलाओं के समूहों और कृषक उत्पादक संघो के उत्पादों की बिक्री के लिए रूरल मार्ट, रूरल हाट और रूरल मार्ट ऑन व्हील्स जैसी पहल के लिए नाबार्ड की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि डिजिटलाइजेशन के दौर में ग्रामीण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्व-सहायता समूहों की भूमिका को विस्तारित किया जाना चाहिए। राज्यपाल ने ग्रामीण विकास उत्सव के शुभारम्भ अवसर पर देश के प्रसिद्ध उत्पादों का अवलोकन किया। उन्होंने अलग-अलग राज्यों के कारीगरों से संवाद करते हुए उनके उत्पादों के संबंध में जानकारी ली। राज्यपाल श्री पटेल ने कारीगरों का उत्साह वर्धन कर शुभकामनाएं और बधाई भी दी। श्री पटेल का नाबार्ड के महाप्रबंधक कमर जावेद ने पुष्प-गुच्छ से स्वागत कर स्मृति-चिन्ह भेंट किया। स्वागत उद्बोधन नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक सुनील कुमार ने दिया। कार्यक्रम को आर.बी.आई. की क्षेत्रीय निदेशक सुश्री रेखा चंदना बेदी, एसबीआई के मुख्य महाप्रबंधक श्री सीएस शर्मा और एसएलबीसी के संयोजक नरसीम सिंह जीरा ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष आर.सी. बेहरा और मध्यान्चल ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष प्रवीण अवस्थी उपस्थित थे।

विज्ञान मेले में एमपी ट्रांसको को मिला द्वितीय स्थान

भोपाल (काप्र)।

विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार थीम पर आयोजित राष्ट्रीय स्तर के विज्ञान मेले 2024 में एम.पी. पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी (एम.पी. ट्रांसको) के स्टॉल को द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने इस उपलब्धि पर ट्रांसको के अधिकारी-कर्मचारियों को बधाई दी है।

महाकौशल विज्ञान परिषद द्वारा वेटरनरी कॉलेज जबलपुर में पहली बार आयोजित महाकौशल विज्ञान मेले में केन्द्र, राज्य, सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों सहित शैक्षणिक संस्थाओं के 111 स्टॉल प्रदर्शित किये गये थे। इसमें से एम.पी. ट्रांसको के स्टॉल को द्वितीय स्थान के लिये चयनित किया गया। चार दिवसीय इस विज्ञान मेले में एम.पी. ट्रांसको के स्टॉल में स्कूल, कॉलेज के विद्यार्थियों से लेकर आम नागरिकों ने काफी दिलचस्पी दिखाई। कुल 3 लाख 25 हजार 949 आगंतुको ने एम.पी. ट्रांसको के स्टॉल में विजिट कर जानकारी हॉसिल की।

एम.पी. ट्रांसको को यह पुरूस्कार मध्यप्रदेश के ट्रांसमिशन नेटवर्क में विभिन्न नवाचार करने, ट्रांसमिशन एलीमेंटस एच.एम.आई तकनीक से नियंत्रित और ऊर्जीकृत करने के साथ ट्रांसमिशन लाइन मेंटेनेन्स में अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करने के विभिन्न मॉडलो के प्रदर्शन और सरल भाषा में आगंतुको को व्याख्या करने की उत्कृष्ट प्रस्तुति के आधार पर दिया गया है। यह चयन देश के प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों, विद्वान शिक्षाविदों और नामी अभियंताओं की कमेटी द्वारा किया गया। एम.पी. पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी के प्रबंध संचालक इंजी. सुनील तिवारी ने इस उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त करते हुये सभी कार्मिकों को बधाई दी है।

उज्जैन में बनेगी प्रदेश की पहली मेडिसिटीः मुख्यमंत्री

भोपाल (काप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि उज्जैन में प्रदेश की पहली मेडिसिटी बनने जा रही है। राज्य सरकार चिकित्सा सेवा और चिकित्सा शिक्षा को और अधिक बेहतर बनाने के लिए गंभीर है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में चिकित्सा सेवा और आयुष के माध्यम से स्वास्थ्य और चिकित्सा को समग्रता में देखते हुए नई अवधारणा पर कार्य हो रहा है। इसके चलते उज्जैन में बनने वाली मेडिसिटी में न केवल मेडिकल कॉलेज रहेगा अपितु नर्सिंग, पैरामेडिकल, अनुसंधान सुविधा, चिकित्सक-विशेषज्ञ और स्टॉफ के आवास सहित संपूर्ण व्यवस्था होगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वे स्वयं इस कैंपस का भूमि-पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पिछले 20 साल में मध्यप्रदेश सरकार ने चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। वर्ष 2004-05 में प्रदेश में मात्र 5 मेडिकल कॉलेज थे, वर्तमान में प्रदेश में 17 मेडिकल कॉलेज संचालित हैं साथ ही 8 कॉलेज निर्माणाधीन हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सिंहस्थ अवधि में लगभग 15 करोड़ की आबादी उज्जैन में होगी। सामान्य समय में भी लगभग 5 से 7 करोड़ यात्री प्रतिवर्ष उज्जैन पधार रहे हैं। अतः यहां मेडिसिटी का बनना उपयोगी और महत्वपूर्ण है। उज्जैन में आकार ले रही मेडिसिटी के लिए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दीं।

मप्र को आर्थिक रूप से सबसे सशक्त राज्य बनाया जाएगाः डॉ. यादव

भोपाल (काप्र)।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश को आर्थिक रूप से देश का सबसे सशक्त राज्य बनाने के लिये प्रदेश में औद्योगिक निवेश बढ़ाने के लिए लगातार कार्य जारी है।

प्रदेश में संभाग स्तर पर उद्योग समूहों को आमंत्रित कर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित किए जा रहे है, साथ ही तमिलनाडु, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में रोड-शो कर निवेशकों और उद्योग समूहों को प्रदेश में अपनी गतिविधियां संचालित करने और उनका विस्तार करने के लिए आमंत्रित किया गया। इन प्रयासों के सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं। अब भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि वैश्विक स्तर से निवेशकों और उद्योग समूहों को प्रदेश में आमंत्रित करने के लिए उनकी इंग्लैंड और जर्मनी की यात्रा प्रस्तावित है, साथ ही अन्य देशों की यात्रा की भी योजना है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मीडिया से चर्चा में यह बात कही।

एक लाख शासकीय पदों के लिये भर्ती प्रक्रिया जारी

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में एक लाख से अधिक शासकीय पदों पर भर्ती की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराने की बात कही थी। इस क्रम में भर्ती प्रक्रिया के विज्ञापन जारी कर लोक सेवा आयोग तथा कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से खाली पदों को भरने की प्रक्रिया आरंभ की जा रही है। निवेशकों से आए प्रस्तावों के अनुरूप निजी क्षेत्र में लगभग ढाई लाख से अधिक पदों पर रोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं। युवाओं को अपनी क्षमता के अनुसार प्रदेश में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध हों, इस उद्देश्य से आई.टी. सेक्टर के साथ ही तकनीकी रूप से दक्षता वाले पाठ्यक्रम भी राज्य सरकार द्वारा संचालित किए जा रहे हैं।

वन्य-जीवों को करंट से बचाने के संबंध में राष्ट्रीय स्तर का मंथन

भोपाल (काप्र)। विद्युत लाइनों से आमजनों, कार्मिकों एवं वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए हरसंभव कोशिश की जा रही है। इसी क्रम में भारतीय वन्य जीवन संस्थान देहरादून ने वन्यजीवों की सुरक्षा, करंट से मृत्यु कम करने को लेकर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला 20 से 22 नवंबर तक आयोजित की है। इसमें पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी से दो कार्मिक शामिल होंगे। कार्यशाला में पर्यावरण सुरक्षा, हाथी व अन्य जीवों की करंट से रक्षा, वन्य जीवों की जोखिम को कम करने के हर संभव प्रयास, बिजली लाइनों के स्वरूप में बदलाव की संभावना और क्रियान्वयन, अंडर ग्राउंड लाइनें एवं केबलीकरण, 33/11 केवी लाइनों की गार्डिंग इत्यादि पर मंथन होगा। पश्चिम क्षेत्र से सुरक्षा शाखा प्रभारी एवं अतिरिक्त मुख्य अभियंता आरके नेगी, वरिष्ठ लाइन परीक्षण सहायक आरएन व्यास भाग ले रहे हैं। इसमें देशभर से पॉवर ट्रांसमिशन एवं बिजली वितरण कंपनी से जुड़े कार्मिकों को आमंत्रित किया गया है।

स्पेशल खबर *मुख्यमंत्री ने किया एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटीज ऑफ एशिया एंड द पैसिफिक के 17वें सम्मेलन का शुभारंभ...*

भगवान श्रीराम और पांडवों की जीत का आधार उनके जीवन मूल्य ही थे

भोपाल (काप्र)।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि भारत का अतीत गौरवशाली रहा है और भारत प्राचीनकाल से ही वैश्विक स्तर पर उच्च शिक्षा का मुख्य केन्द्र रहा।

कई देशों के विद्यार्थियों, राजकुमारों ने तक्षशिला, नालंदा जैसे भारत के विश्वविद्यालयों में शिक्षा ग्रहण की। लेकिन ऐतिहासकि रूप से हमें ऐसा कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता, जिसमें भारत में शिक्षा ग्रहण किए किसी व्यक्ति अथवा सत्ताधीश ने अन्य राज्य पर आक्रमण किया हो। यह तथ्य प्राचीन काल से चली आ रही हमारी शिक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ जीवन मूल्यों और नैतिक मूल्यों को दर्शाता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंगलवार को होटल ताज में एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटीज ऑफ एशिया एंड द पैसिफिक के 17वें सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का

शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि उच्च शिक्षा का बदलता स्वरूप और हमारे जीवन मूल्य विषय पर आयोजित यह सम्मेलन सम-सामयिक महत्व का है। अतीत से लेकर वर्तमान तक की कई घटनाएं जीवन मूल्यों के प्रति दृष्टिकोण की भिन्नता के परिणाम स्वरूप ही घटित हुईं। रामायण काल में रावण हो या महाभारत काल में कौरव, योग्यता और क्षमता में कोई भी कम नहीं था, लेकिन उनके जीवन मूल्य और नैतिक मूल्य उचित नहीं थे, इसी कारण उन्हें कभी सम्मान नहीं मिला और वे समाज में तथा इतिहास में सदैव नकारे गए। कर्ण की योग्यता अद्भुत थी, लेकिन उनकी दृष्टि, प्रतिशोध, जिद और नकारात्मक भाव ने उन्हें पतन की ओर अग्रसर किया। इसी प्रकार के उदाहरण हमें सोने की लंका बनाने वाले रावण के भी प्राप्त होते हैं। सभी प्रकार के वैभव और सामर्थ्य होने के बाद भी वे कभी स्वीकारे नहीं गए और नैतिक मूल्यों के आधार पर ही वनवासी श्रीराम ने उन्हें परास्त किया। अर्थात् यह नैतिक मूल्यों और जीवन मूल्यों की ही विजय थी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने रूस-यूक्रेन युद्ध और इजराइल के संघर्ष का उल्लेख करते हुए कहा कि हमारे आदर्शों और जीवन मूल्यों का ही परिणाम है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी इन संघर्षों में भी शांति के लिए प्रयास करते दिखाई देते हैं। यह भारतीय जीवन मूल्यों के सामर्थ्य को दर्शाता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वर्ष 2020 से लागू नई शिक्षा नीति के माध्यम से पढ़ने और सीखने की प्रक्रिया को अधिक लचीला, सरल और रूचिपूर्ण बनाते हुए विद्यार्थियों को विभिन्न संकायों के विषयों के अध्ययन की सुविधा प्रदान की गई है। अध्ययन प्रक्रिया को आयु के बंधन से मुक्त करते हुए क्रेडिट प्रदान करने जैसे नवाचार भी प्रदेश में किए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटीज ऑफ एशिया एंड द पैसिफिक को मध्यप्रदेश में अपनी गतिविधियों के विस्तार के लिए आमंत्रित किया। जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी के चांसलर हरिमोहन गुप्ता ने बताया कि 35 देशों में फैले एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटीज ऑफ एशिया एंड द पैसिफिक का सम्मेलन भारत में पहली बार हो रहा है। एसोसिएशन मध्यप्रदेश में उच्च शिक्षा और कौशल विकास पर केन्द्रित वैश्विक संस्थाओं की स्थापना कर विद्यार्थियों को वैश्विक स्तर की शिक्षा देश में ही उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा अनुपम राजन, शिक्षाविद अनूप स्वरूप और विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि तथा विषय-विशेषज्ञ उपस्थित थे।